(c) if so, what steps have been or are being taken by Government to ensure that the uncensored film is not exhibited and exploitation of the victims is prevented?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) No sir. The film was not shown in the Indian International Film Festival held at Bombay in January, 1995.

(b) Government has seen the news item.

(c) Only films certified by the Central Board of Film Certification under the provisions of the Cinematograph Act, 1952 and the guidelines issued thereunder can be exhibited in public. The responsibility for enforcing the provisions of the Act with regard to exhibition of films rests with the State Governments/Union Territory Administrations.

Electricity rates for different categories of consumers

308. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the State-wise electricity rates for different categories of consumers of electricity, including the industrial, domestic, commercial and agricultural, as on 1.1.1994 and as on date;

(b) the State-wise electriicty generation and consumption by different categories of consumers during 1992-93 and 1993-94;

(c) the State-wise revenue realisable and actual realisation from different categories of consumers on account of consumption of electricity during 1992-93 and 1993-94; and

(d) the State-wise estimated loss on the distribution of electricity to domestic consumers and agriculturists, in terms of average cost of electricity distribution, during 1992-93 and 1993-94?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) The State-wise electricity rates for different categories of consumers of electricity as on 1.1.1994 and 1.3.1995 are enclosed at Annexures respectively. (*See* Appendix 173, Annexure No. 6)

(b) A statement indicating the state-wise including BBMB and DVC power generated during the years 1992-93 and 1993-94, is enclosed at Annexures. [*See* Appendix 173, Annexure No. 6]. State-wise/category-wise (utilities only) electricity sales to different categories of consumers during the year 1992-93 and 1993-94 are enclosed at Annexures [*See* Appendix 173, Annexure No. 6) and Annexures respectively.

(c) A statement indicating the revenue realisation by the State Electricity Boards or the year 1992-93 is enclosed at Annexures [See Appendix 173, Annexure No. 6].

(d) The estimated losses for supply of power to the domestic and agricultural consumers during the year 1992-93 are enclosed at Annexures (See Appendix 173, Annexure No. 6).

गुजरात और महाराष्ट्र में विद्युत की स्थिति

309. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और महाराष्ट्र में विद्युत के उत्पादन और उसकी मांग में कोई अंतर है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत की मांग और उसके उत्पादन का ब्यौरा क्या है तथा अंतर को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये है/उठाए जावेंगे ;

(ग) क्या सरकार विद्युत उत्पादन तथा विद्युत वितरण व्यवस्था का निजीकरण करने का विचार रखती है ;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं, जहां विद्युत उत्पादन का निजीकरण कर दिया गया है तथा इस संबंध में गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है ; और

(ङ) क्या सरकार गुजरात में गैस-आधारित विद्युत केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती ऊर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) और (ख) गुजरात और महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान वस्तुतः विद्युत सप्लाई की स्थिति का ब्यौरा निम्नवत है :—

(सभी आंकड़े निवल मि०यू० में)

	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95 (जनवरी, 95 तक)
गुजरात :				
आवश्यकता	25505	26500	29860	25970
उपलब्धता	24417	25712	28502	24957
कमी	1088	788	1358	1013
प्रतिशत	4.3	3.0	4.5	3.9
महाराष्ट्र :				
आवश्यकता	42070	43970	44895	40520
उपलब्धता	40166	41387	43514	39838
कमी	1904	2583	1381	682
प्रतिशत	4.5	5.9	3.1	1.6

गुजरात एवं महाराष्ट्र में विद्युत की मांग और उपलब्धता के बीच अन्तर को समाप्त करने हेतु विद्युत की उपलब्धता में सुधार किए जाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं:— नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, अल्पावधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा का कम करना, बेहतर मांग प्रबंध एवं ऊर्जा संवर्धन उपायों का क्रियान्वयन, अधिशेष ऊर्जा वाले क्षेत्रों से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा का अंतरण करना और विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देना।

(ग) केन्द्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राज्य बिजली बोर्डों के पास संसाधनों की कमी एवं विद्युत की तेजी से बढ़ती हुई मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को समाप्त करने को मद्देनजर रखते हुए विद्युत उत्पादन एवं वितरण में क्षमता अभिवृद्धि हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने के उद्देश्य से विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा अधिकाधिक निवेश किए जाने को प्रोत्साहन देने के लिए 1991 में एक नीति तैयार की गई थी और यह इस समय क्रियान्वयनाधीन है।

(घ) अधिकांश राज्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अनुरोध किया है और गुजरात तथा मध्य प्रदेश समेत विद्युत उत्पादन परियोजनाएं अधिष्ठापित की जा रही हैं। इन राज्यों के नाम निम्नवत हैं :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम
4. बिहार
5. दिल्ली
6. गुजरात
7. हरियाणा
8. हिमाचल प्रदेश
9. केरल
10. कर्नाटक
11. महाराष्ट्र
12. मध्य प्रदेश
13. उड़ीसा
14. राजस्थान
15. तमिलनाडु
16. उत्तर प्रदेश
17. पश्चिम बंगाल

गुजरात में 2565 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता वाली 5 विद्युत परियोजनाएं पहले ही निजी क्षेत्र को सौंपी जा चुकी हैं। उनका कुछेक अन्य परियोजनाओं को भी बोली के माध्यम से निजी क्षेत्र को सौंपे जाने का प्रस्ताव है।

मध्य प्रदेश में 56.52 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता हेतु 12 विद्युत परियोजनाएं निजी क्षेत्र को सौंपी गई है और राज्य सरकार द्वारा बोली के माध्यम से कुछ अन्य परियोजनाएं सौंपे जाने की भी प्रत्याशा है।

(ङ) गांधार में गैस-आधारित विद्युत संयंत्र अधिष्ठापित किया गया है, जिसमें 131— मेगावाट के 3 गैस टर्बाइन शामिल हैं। इस केन्द्र के स्टीम टर्बाइन यूनिट को मार्च, 1995 में चालू किए जाने की आशा है। इसके अलावा, दो परियोजनाएं यथा गांधार (पागुथन) सीसी-जीटी-655 मेगावाट और बड़ौदा जिले में गुजरात इण्डस्ट्रियल पावर कम्पनी लि. 145 मेगावाट के विद्युत संयंत्र हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

Inadequate coal supply

310. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether power generation has been decreasing in the country particularly in Uttar Pradesh due to inadequate supply of coal during the last three years;

(b) if so, the reasons for the reduction in coal supply; and

(c) the measures taken by Government to remove shortage in the supply of coal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) No, Sir.

(b) The question does not arise.

(c) The position of coal supply to all the thermal power stations in the country including those in Uttar Pradesh, is kept under constant review including at the high level interdepartmental weekly meetings, and the remedial actions are taken from time to time.

कहलगांव ताप विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन

311. **श्री जनार्दन यादव** : क्या विद्युत मंत्री 13 दिसम्बर, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं. 1048 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कहलगांव ताप विद्युत परियोजना में इस समय कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जा रहा है,